भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

(21–22–23 सितम्बर, 2007)
स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे सभागार
पं0 दीनदयाल परिसर (भोपाल)

राम सेतु पर प्रस्ताव
(क्षमायाचना, राम को स्वीकारें,
सेतु समुद्रम को राष्ट्रीय धरोहर की घोषणा)

भारतीय जनता पार्टी, संप्रग सरकार द्वारा रामसेतु के मामले में जिस तरह का गोलमाल किया जा रहा है, उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। पहला तो यह कि सरकार ने आचार्यों, सुनामी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, विद्वानों तथा पूर्व–जस्टिस कृष्ण अय्यर व पूर्व–जस्टिस, पद्म भूषण के. टी. थामस जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उचित राय की उपेक्षा की। साथ ही, इसने रामसेतु को नष्ट होने से बचाने हेतु, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के एलाइनमेंट को बदलने के लिए समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रस्तुत 36 लाख हस्ताक्षरित आवेदन को कूड़ेदान में डाल दिया। यहां तक कि सरकार, उस वक्त भी इस मामले की गंभीरता समझने में नाकाम रही, जब राज्य सभा में बहस के दौरान पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की थी। सरकार को दलों से ऊपर उठकर अनेक महत्वपूर्ण राजनेताओं के उन बयानों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें श्री राम को राष्ट्रीय महापुरुष ही नहीं, बल्कि ईश्वर का अवतार स्वीकार किया है।

दूसरा– जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठा, तो सरकार ने बड़ी निर्लज्जता से एक हलफनामा दायर किया, जिसमें श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। यह हलफनामा राष्ट्र और परंपराओं पर हमला है और वास्तव में यह स्वतंत्रता संग्राम का भी अपमान है, जिसका मकसद, महात्मा गांधी के अनुसार, रामराज्य की स्थापना करना था। सच तो यह है कि संप्रग सरकार लोगों की भावनाओं का जरा भी सम्मान नहीं करती। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जनता पुल को सेतु मंदिर, राम सेतु और आदमपुल, एडम ब्रिज, आदि सेतु के रूप में देखती है। तीसरा, ईशनिंदात्मक हलफनामे को पूरी तरह से वापस लेने व देश से माफी मांगने के बजाय, संप्रग सरकार यह जानने में भी असफल रही कि हलफनामें को किसने तैयार किया और किस स्तर पर इसे स्वीकृति मिली? वास्तव में सरकार को श्री राम के इस घोर अनादर की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सरकार को सभी 'ड्रेजिंग' कार्य तत्काल बंद कर देने चाहिए और उसे ऐसे उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे करोड़ों देशवासियों की आहत भावना शांत हो। दूसरी तरफ, सरकार पूरक हलफनामे दाखिल करने की कोशिश कर रही है। जहाजरानी मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

करना चाहता है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के भीतर अतिशय भ्रम, इस बात का संकेत देता है कि पार्टी के विभिन्न नेताओं के बीच आरोप–प्रत्यारोप का युद्ध जारी है। एक ऐसी सरकार जिसे अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, परंपरा, साहित्य और राम जैसे महापुरुषों के कृत्यों तथा वाल्मिक जैसे संतों, जिन्होंने सनातन काल से राष्ट्र के मूल्यों को पोषित किया, से पूर्णत अनभिज्ञ है और उसे अस्वीकार भी करती है, वह शासन में रहने के काबिल नहीं।

भाजपा समाज के सभी वर्गों का आभार ज्ञापित करती है, जिन्होंने राम सेतु के तोड़े जाने का दृढ़ता से विरोध किया और मांग की कि इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाय। भाजपा इस मांग को पुनः दुहराती है कि राम सेतु को विश्व धरोहर घोषित किया जाय और उन सभी गतिविधियों को बंद किया जाय, जिससे पुल नष्ट होता हो या होने की संभावना हो।

भाजपा उन वक्तव्यों की भी गंभीर निंदा करती है, जिसमें प्रोजेक्ट के रिएलाइनमेंट को अराष्ट्रीय कहा गया है। पार्टी उन विभाजनकारी कथनों/तर्कों को भी नामंजूर करती है, जो कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी व तर्क–विर्तक के जरिए देशवासियों को भौगोलिक, भाषाई और जातीय आधार पर बांटने की कोशिश करती है। इन सिद्धांतों को विद्वानों तथा जनता ने पूर्णतः नकार दिया है। भारत एक जन और एक राष्ट्र है तथा पार्टी विघटनकारी शक्तियों की शरारतों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी।

यदि संप्रग सरकार के घटक दल राम का अपमान जारी रखते हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार का समर्थन इन कथनों से है तथा वह इस राष्ट्रीय अपमान से आंखें मूद रही है। भाजपा ऐसे तत्वों को चेतावनी देती है कि वे इस तरह के बयान जारी करने से बाज आएं, जो राष्ट्रीय ताने–बाने को कमजोर करता है। यही नहीं, इसका घातक असर देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ेगा, जिसके लिए केंद्र की कांग्रेस–नीत सरकार अकेली जिम्मेदार होगी।

राम सेतु की रक्षा, सरंक्षण व राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सेतु समुद्रम को घोषित किए जाने का आंदोलन, रामेश्वरम् राम सेतु रक्षा मंच द्वारा चलाया जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, जिसे पार्टियों से ऊपर उठकर जनता एवं धार्मिक मतावलंबियों का पूर्ण समर्थन हासिल है। पार्टी समिति को इस मामले में पूर्ण सहायता प्रदान करेगी। पार्टी राम सेतु को बतौर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करने के लिए पूर्णरूपेण समर्पित है। भाजपा संप्रग सरकार से बिना शर्त क्षमायाचना की मांग करती है और यह भी मांग करती है कि ऐसे अपमानजनक हलफनामे के प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी तय करे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com